(ग) पिछले तीन वर्षों में क्या लक्ष्य रखे गये और इनकी उपलब्धि क्या रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दक्षिण के राज्यों की तुलना में समस्त हिन्दी भाषी क्षेत्रों में पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही है । उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति सभी हिन्दी राज्यों के समान ही है ।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम जो इससे पूर्व प्रमुख कार्यनीति थी, को धीरे-धीरे हटा कर पूर्ण साक्षरता अभियान को प्रमुख कार्य नीति के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया था । बीच के वर्षों में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम की परियोजनाओं को पूरी तरह से बन्द करके अभियान दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई थी, जिसके कारण कार्यक्रम की गति तथा प्रगति में गिरावट आ गई । उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक परियोजनाओं को प्रशासनिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये । तथापि, अब तक राज्य के आठ जिलों अर्थात् फतेहपुर, चमोली, देहरादून, अल्मोड़ा, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा बिजनौर में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किये गये हैं : 12 और जिलों के भी प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

Transfer of surplus Teachers in Kendriya Vidyalayas

584. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 550 teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan have been rendered surplus;

(b) if so, number of such teachers, category-wise and region-wise;

(c) whether AIKVTA has challenged the basis of their being declared SURPLUS; and

(d) if so, the reaction of the Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (d) The Kendriya Vidyalaya Sangathan has an overall shortage of regular teachers and as such the question of declaring any teacher as "SURPLUS" to the organisation does not arise. However, in any particular academic year, the number of teachers in a specific school could be in excess of the sanctioned strength for short intervals of time for various reasons, such as reduction in staff strength due to decrease in number of sections, promotions, transfers and delays in joining new positions. Adjusting the number of teachers in any particular school through inter-regional and intra-regional transfers, and by reallocation of costs amongst schools according to emerging needs is a continuing process.

गुजरात में आपरेशन "ब्लैक-बोर्ड"

585. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में "आपरेशन ब्लैक-बोर्ड" के अन्तर्गत कितने अध्ययन केन्द्रों का निर्माण किया गया है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत और धन-राशि दिए जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शलजा) : (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत कोई अध्ययन केन्द्र नहीं खोले गए। तथापि, इस योजना के तहत 12393 प्राथमिक स्कूल (शत-प्रतिशत) शामिल कर लिए गए हैं ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक 2829.08 लाख रु० खर्च हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Supreme Court Verdict on Capitation Fee

586. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the Supreme Court Judgement regarding the Andhra Pradesh capitation fee case;

(b) if so, what steps are proposed to be taken to counter the ill-effect of declaring capitation fee, subject to norms fixed by the Apex Court, legal; in view of Government's Commitment to abolish capitation fees; and

(c) whether Government propose to consider amending the Constitution f necessary, to plug any loopholes n related provisions of the Constitution which were responsible for the udgement?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Government is committed to implement the judgement of the Supreme Court by evolving suitable criteria and guidelined in consultation with the concerned authorities.

Vivekanand Mahila College

587. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the lady teachers of Vivekanand Mahila College raised their voice against the alleged bungling with their P. F. money by Delhi Administration which is responsible for administering the College;

(b) whether their demonstration was lathi charged; and

(c) if so, whether any probe into the allegation of bungling with P.F. money and the lathi charge has been ordered?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) The information is being collected and shall be laid on the Table of the Sabha.

Setting up of Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit University

588. SHRI V. RAJESHWAR RAO:

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Un-